

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 21 मार्च , 2021

विषय- प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना (F.P.I.S.) स्कीम में प्रदान की जाने वाली राशि को दुगुना किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) सं०-9/2012 देविका विश्वास बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दि०-14.09.2016 एवम् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11017/C/1/2012-FP (Pt) दि०-04.10.2016 के अनुपालन में आपके पत्र संख्या-3प/प०क०/20/ 2018/7620 दि०-25.03.2020, पत्र संख्या-2815 दि०-13.10.2021, पत्र संख्या-24169 दि०-02.11.2021, पत्र संख्या-26394 दि०-01.12.2021 पत्र संख्या-2489 दि०-01.02.2022 के क्रम में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना के अन्तर्गत नसबन्दी के लाभार्थियों को नसबन्दी के कारण उत्पन्न हुई जटिलता/असफलता/मृत्यु के प्रकरणों में वर्तमान में प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की धनराशि दोगुनी की जाती है।

2. परिवार नियोजन इन्डमिनिटी योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का विवरण निम्नवत रहेगा :-

Section	Coverage	Limits			
		GOI Share		State share	
IA	Death following sterilization (inclusive of death during process of sterilization operation) in hospital or within 7 days from the date of discharge from hospital.	Rs. 2,00,000/-		Rs. 2,00,000/-	
IB	Death following sterilization within 8-30 days from the date of discharge from hospital.	Rs. 50,000/-		Rs. 50,000/-	
IC	Failure of sterilization.	Rs. 30,000/-		Rs. 30,000/-	
ID	Cost of treatment in hospital and upto 60 days arising out of complication following sterilization operation (inclusive of complication during process of sterilization operation) from the date of discharge.	Actually not exceeding Rs. 25,000/-		Actually not exceeding Rs. 25,000/-	
II	Indemnity per doctor/health facilities but not more than 4 in a year.	Upto Rs. 2,00,000/-	per claim	Upto Rs. 2,00,000/-	per claim

3. उपरोक्त के क्रम में नई दर से लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का व्यय भार सुसंगत मद, जिसमें केन्द्रांश के रूप में 50 प्रतिशत एवं राज्यांश के रूप में 50 प्रतिशत की दर से वहन किया जाता है," से किया जायेगा। तदनुसार भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल फार फैमिली प्लानिंग इन्डैमिनिटी स्कीम के निर्देशों का अनुपालन करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या- 170 (1)/XXVIII(3)22-75/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई, दिल्ली।
2. महालेखाकार, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जनपदीय पुरुष/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।